nwda.gov.in

हरनंदी के प्रदूषण पर अंकुश से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी

प्रयागराज और हरिद्वार में घाटों का भी किया जाएगा विकास

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने हरनंदी नदी (हिंडन) के प्रदूषण को घटाने और कुंभ की तैयारियों को लेकर आठ नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत 638 करोड़ रुपये होगी। मिशन के महानिदेशक जी. अशोक कुमार की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति की मंगलवार को हुई बैठक में इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

- स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने 638 करोड़ रुपये के आठ प्रोजेक्ट मंजूर
- मध्य प्रदेश और बिहार में लगेंगे एसटीपी

यमुना की सहायक नदी हरनंदी के प्रदूषण की रोकथाम के लिए 407.39 करोड़ की लागत से शामली में चार नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। ये परियोजनाएं व्यापक हरनंदी पुनरुत्थान योजना का हिस्सा हैं। हरनंदी नदी को पहली प्राथमिकता वाली प्रदूषित नदियों की श्रेणी में रखा गया है। हरनंदी की प्रमुख सहायक नदी कृष्णी शामली में बड़ी मात्रा में प्रदूषित जल को हरनंदी में उड़ेलती है, जिसके चलते इस नदी का प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है।

शामली में जो चार परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, उनमें 50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट व पांच केएलडी के सेप्टेज को ट्रीटमेंट फैसिलिटी (बाबरी और बंटीखेड़ा गांव), बनट कस्बे में 50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला एसटीपी, पांच केएलडी के सेप्टेज को ट्रीटमेंट फैसिलिटी, शामली कस्बे में चार करोड़ लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला एसटीपी व 20 केएलडी का सेप्टेट को ट्रीटमेंट फैसिलिटी और थाना भवन कस्बे में एक करोड़ लीटर प्रतिदन क्षमता वाला एसटीपी और सेप्टेज फैसिलिटी शामिल हैं।

2025 में प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों के लिए शहर में सात घाटों के विकास की एक परियोजना को मंजूरी दी गई है। समिति ने जिन घाटों के विकास को मंजूरी दी है, उनमें दशाश्वमेध, किला, नौकायन, ज्ञान गंगा आश्रम, सरस्वती महेवा और रसूलाबाद शामिल हैं। इन घाटों में स्नान क्षेत्र, चेंज रूम, सभी की पहुंच वाले रैंप, पेयजल के प्वाइंट, फ्लड लाइट और कुछ कियोस्क लगाए जाएंगे।

बिहार और मध्य प्रदेश में भी एक-एक सीवेज मैनेजमेंट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। बिहार में तीन एसटीपी लगाए जाएंगे, जबकि मध्य प्रदेश में 2.2 करोड़ लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला एसटीपी स्थापित होगा। घाट विकास की एक अन्य परियोजना हरिद्वार के लिए है। यहां 2.12 करोड़ रुपये की लागत से अखंड परम धाम घाट का विकास किया जाएगा। महानिदेशक अशोक कुमार ने राज्यों से कहा है कि वे एसटीपी वाले क्षेत्रों में सोलर फार्मिंग को बढावा दें तथा सौर ऊर्जा से ही निर्मल जल केंद्र यानी एसटीपी के संचालन की कोशिश करें।